सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • 8 MAY TO 14 MAY 2020 • VOLUME-35 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD
No Filing Charges &
*Pay money after the visa
IELTS | STUDY ABROAD

CANADA AUSTRALIA USA
U.K SINGAPORE EUROPE

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.
*T&C apply

जो जहां खड़ा था वहीं हुआ बेहोश

गैस रिसाव, आरआर वेंकटपुरा इलाके में हृदयविदारक दृश्य

मनुष्य ही नहीं पशु भी हुए अचेत

विशाखापत्तनम, (वार्ता): आंध, प्रदेश में विशाखापत्तनम के आर आर वेंकटपुरम गांव स्थित एलजी पॉलिमर रसायन संयंत्र में गुरूवार तड़के जहरीली गैस रिसने की घटना के बाद इलाके का दृश्य हृदयविदारक नजर आया जब महिलाओं तथा बच्चों समेत काफी संख्या मे लोगों के साथ ही पशु-पक्षी अचेत पड़ पाये गये और उनके मुंह से झाग निकलता देखा गया। गैस रिसाव की घटना में अब तक कम से कम आठ लोगों के मौत की रिपोर्टें आयी है। इसके अलावा सैंकड़ की संख्या में प्रभावित लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है जिनमें 15 की हालत गंभीर बनी हुई है। गांव की सड़कों पर कई लोग मृत अथवा अचेत पड़े थे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और जीवन के लिए संघर्ष करते दिखाई दिए। बाद में उन सभी को अस्पताल ले जाया गया। तड़के करीब तीन बजे जब संयंत्र से गैस रिसाव शुरू हुआ और उसके बाद पास ही के आरआर वेंकटकपुरम गांव के कुछ लोगों ने सांस फूलने, आंखों में जलन और चक्कर आने की शिकायत महसूस की। गांव के निवासी वी रामा कृष्णा ने मीडिया को बताया कि जैसे ही कुछ घटित होने का अहसास हुआ, वे सब घरों से बाहर निकल पड़ और सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। रामकृष्णा ने कहा कि उन्होंने कई लोगों को बेहोश देखा और उनके मुंह से झाग निकलते देखा। उनमें से कुछ की मृत्यु हो चुकी थी और कुछ की हालत गंभीर नजर आ रही थी। खूंटे से बंधे मवेशियों, कुछ भैंसों के अलावा कुत्तों, सुअरों और सैकड़ की संख्या में पक्षी भी अचेत पड़ थे।के जी अस्पताल और अन्य अस्पतालों में भी अफरातफरी का माहौल था, जहां माता-पिता अपने बच्चों की तलाश करते और चीत्कार करते दिखे।जहरीली गैस के असर का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि संयंत्र के आसपास के क्षेत्रों के पेड़-पौधे भी मुरझा गये। गांव के एक निवासी एस अप्पा राव ने कहा कि गैस रिसाव की इस घटना ने उस भोपाल गैस त्रासदी की याद दिला दी, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की जानें गयी थी।संयंत्र की स्थापना 1970 में की गयी थी, तब यह एक उजाड़ इलाका था, उस समय 'हिन्दुस्तान पॉलिमर' के नाम से संयंत्र विजय माल्या के स्वामित्व में था। बाद में 1997 में दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी पॉलीमर्स ने संयंत्र को अपने अधिग्रहण में ले लिया।

प्रधानमंत्री ने स्थिति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक रासायनिक संयंत्र में गैस लीक होने के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री ने गैस लीक होने के बाद पैदा हुए हालात के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे बुलाई है।प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय और एनडीएमए के अधिकारियों से स्थिति के संबंध में बात की है जो स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं ।उन्होंने कहा, ''मैं सभी की सुरक्षा और विशाखापत्तनम के लोगों की कुशलक्षेम की प्रार्थना करता हूं । ''पीएमओ के ट्वीट के अनुसार, मोदी ने विशाखापत्तनम की स्थिति पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी से बात की और उन्हें हर तरह की मदद और समर्थन देने का आश्वासन दिया ।

राष्ट्रपति ने किया शोक व्यक्त

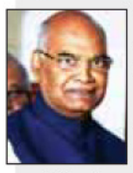

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भी इस मामले पर ट्वीट कर लिखा, "विशाखापट्टनम के पास एक प्लांट में गैस के रिसाव की ख़बर से दुखी हूं जिसने कई लोगों की जान ले ली। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। मैं घायलों के ठीक होने और सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं।"

गैस रिसाव की घटना परेशान करने वाली : शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रसायनिक संयंत्र से गैस रिसाव को बृहस्पतिवार को परेशान करने वाला बताया और कहा कि केंद्र सरकार स्थित पर पैनी निगाह रख रही है ।शाह ने कहा कि वह विशाखापत्तनम के लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गृह मंत्री ने ट्वीट किया, विशाखापत्तनम की घटना परेशान करने वाली है। एनडीएमए के अफसरों और संबंधित अधिकारियों से बात की है। हम निरंतर स्थिति पर नजर रख रहे हैं ।केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव से बात की है और पुलिस महानिदेशक को हालात का जायजा लेने का निर्देश दिया है ।रेड्डी ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीमों को पीड़ितों को जरूरी मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

लीक हुई गैस स्टाइरीन को 181 साल पहले खोजा गया था

विशाखापट्टनम, (एजेंसी): आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम में गुरुवार तड़के एलजी कम्पनी के केमिकल प्लांट से जो गैस लीक हुई है उसका नाम स्टाइरीन गैस है। पुलिस कमिशनर राजीव कुमार मीणा के मुताबिक शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, प्लांट से स्टाइरीन गैस का रिसाव हो रहा था और इलाके के लोग अनजान थे। डॉक्टरों का कहना है कि स्टाइरीन एक न्यूरो-टॉक्सिन और दम घोंटू गैस है जिससे सिर्फ दस मिनट में शरीर शिथिल पड़ जाता है और मौत हो जाती है। इस गैस पर हुई स्टडी में इसे कैंसर और जेनेटिक म्यूटेशन का कारण भी बताया गया है। दुनिया में स्टाइरीन को पहली बार करीब 181 साल पहले यूरोप के वैज्ञानिकों ने पहचाना। 1839 में, जर्मन विज्ञानी एडुअर्ड साइमन ने अमेरिकी स्वीटगम पेड़ से निकली राल या रेजिन (वाष्प या स्ट्रेक्स) से एक वाष्पशील तरल को अलग किया। उन्होंने इसे "स्टाइलोल" (अब स्टाइरीन) नाम दिया।उन्होंने यह भी देखा कि जब स्टाइलोल को हवा, प्रकाश या गर्मी के संपर्क में लाया गया तो यह धीरे-धीरे एक कठोर, रबड़ जैसे पदार्थ में बदल गया, जिसे उन्होंने "स्टाइलर ऑक्साइड" कहा। 1845 में जर्मन केमिस्ट ऑगस्ट हॉफमैन और उनके छात्र जॉन बेलीथ ने स्टाइलिन के फार्मूला दिया जो C_8H_8 के नाम से मशहूर हुआ। इसमें कार्बन के 8 और हाइड्रोजन के 8 अणु आपस में गुंथे होते हैं।

सांस में जाने पर तत्काल प्रभाव : स्टाइरीन गैस नाक में जाने पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऊबकाई के साथ और आंखों में जलन हो सकती है। सांस में जाने पर यह कुछ ही मिनटों में हमारी श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है और उल्टी, जलन और त्वचा पर चकत्ते पैदा कर सकती है। रोग नियंत्रण केंद्र (सीडीसी) के मुताबिक गैस का अल्पकालिक जोखिम छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए घातक हो सकता है। आंखों में जलन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रभाव (जैसे पेट खराब होना) और टिश्यूज की ऊपरी सतह में जलन हो सकती है। यह शरीर के कोमल अंगों के टिश्यूज के अस्तर को नष्ट करने की क्षमता रखती है और इसके कारण रक्तस्राव हो सकता है।

भोपाल की मिक बनाम विशाखापट्टनम की स्टाइरीन गैस

मध्यप्रदेश के भोपाल में अमेरिकी यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाना में 3 दिसंबर 1984 को 42 हजार किलो जहरीली गैस का रिसाव होने से करीब 15 हजार से अधिक लोगों की जान गई थी और लाखों प्रभावित हुए थे। यह गैस भी एक आर्गनिक कम्पाउंड से निकली मिथाइल आईसोसाइनेट या मिक गैस थी जो कीटनाशक और पॉली प्रॉडक्ट बनाने की काम आती है। इतने साल के बाद भी इस गैस का असर पुराने भोपाल शहर के लोगों में देखा जा सकता है। हजारों लोग स्थायी अपंगता, कैंसर और नेत्रहीनता का शिकार हो गए। इस गैस ने अजन्में बच्चों तक को प्रभावित किया था। जहां विशाखापट्टनम प्लांट से निकली स्टाइरीन का रिएक्शन टाइम 10 मिनट का है, वहीं मिक गैस महज कुछ सेकंड में जान चली जाती है।

लम्बे समय तक प्रभाव : यहां तक कि जो लोग स्टाइरीन की घातक चपेट में आने के बाद बच जाते हैं, उन्हें बाद में इसके विषैले प्रभावों के साथ जीना पड़ सकता है। न्यूरोटॉक्सिन होने कारण इसका तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है और यह सिरदर्द, थकान, कमजोरी और अवसाद, नर्वस सिस्टम की शिथिलता का कारण बन सकता है। इसके लम्बे प्रभाव के कारण हाथ और पैर जैसे सुन्नता, आंखों को नुकसान, सुनाई न देना और त्वचा पर डर्मीटाइटिस जैसी बीमारी देखने को मिलती है।

लीक हुई गैस से प्रभावित दो बच्चे अस्पताल में उपचाराधीन।

एसएसपी कार्यालय कपूरथला ने भाजपा नेता के बेटे को ब्यान दर्ज कराने के लिए बुलाया

जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

कोरोना महामारी ने पुरे विश्व को तो हिलाकर रखा ही परन्तु इस बिमारी ने कई उद्योगपतिओं की भी मुश्किल बढ़ाने का काम किया है जैसे की रोज़ सुनने में आ रहा है बड़े-बड़े मीडिया घराने इश्तिहार का काम न मिलने से हाशिये पर चले गये और कई उद्योगपति मुलाज़िमों को पगार देने में असमर्थ दिख रहे है इसी लड़ी वार में जालंधर- फगवाड़ा रोड पर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी काफी सुर्खियों में रही उसका सुर्खियों में रहने का मुख्य कारण पिछले दिनों यहाँ एक महिला छात्र का कोरोना पॉजिटिव आना परन्तु आज की तारीख में वो महिला छात्र भी कपूरथला हॉस्पिटल से इलाज करवाने के बाद ठीक हो गई पर कुछ समाज सेवी और कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा पिछले दिनों प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किये गए थे और लिखित शिकायतें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर उच्च अधिकारिओं तक को की गयी जिसमे एक शिकायत पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे साहिल सांपला ने माननीय हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर

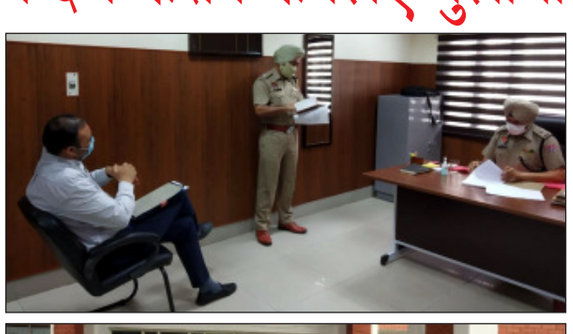

की गयी जिसकों सुनने के बाद माननीय हाईकोर्ट द्वारा यह आर्डर किया गया की आप पहले शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों को दर्ज कराये अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती तो मेरे पास दोबारा आने के लिए स्वतंत्र है।

माननीय हाई कोर्ट के आदेशों की पलना करते हुए साहिल सांपला द्वारा एसएसपी कपूरथला को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गयी जिसमे एसएसपी कपूरथला द्वारा उन्हें ब्यान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया जिस पर की साहिल सांपला द्वारा आदेशों की पालना करते हुए ब्यान दर्ज कराये गए अब आने वाले दिनों में देखना होगा की प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करेगा ?

गैस से प्रभावित अपनी बच्ची को उठाकर अस्पताल ले जाती महिला।

राहुल ने प्रभावित लोगों की मदद की अपील की

नई दिल्ली, (एजेंसी): कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस रिसाव की घटना पर दुख जताते हुए बृहस्पतिवार को पार्टी के स्थानीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद करें। उन्होंने ट्वीट किया, '' मैं विजाग (आंध्र प्रदेश) में गैस लीक के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। मैं इलाके के कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद करें।' 'गांधी ने कहा, ''पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। मैं अस्पताल में भर्ती लोगों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। विशाखापट्टनम में तड़के एक रासायनिक संयंत्र से गैस का रिसाव हो जाने के कारण छह लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

रायगढ़ पेपर मिल में जहरीली गैस लीक, 7 मजदूर बीमार

रायगढ़, (एजेंसी): विशाखापत्तनम में हुए गैस लीकेज जैसी घटना छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी हुई है। हालांकि यह घटना बुधवार की है। यहां तेतला गांव में स्थित एक पेपर मिल में जहरीली गैस लीक होने से 7 मजदूरों की तबियत बिगड़ गई। सभी को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें 3 की हालत नाजुक होने पर रायपुर रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी एक दिन तक मिल के मालिक ने छिपाई रखी। गुरुवार को इसका खुलासा हुआ तो डीएम, एसएसपी समेत कई अफसर मिल और अस्पताल पहुंच गए। मामले में मिल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। रायगढ़ एसएसपी के मुताबिक मिल में टंकी साफ करते समय यह हादसा हुआ। मिल मालिक के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

घटना छिपाने पर मिल मालिक के खिलाफ एफआईआर

गैस की चपेट में आए ये मजदूर : एसएसपी के मुताबिक पेपर मिल को चालू करने के लिए साफ सफाई काम चल रहा था। मजदूर फैक्ट्री के अंदर रिसायकल चेंबर की सफाई करने पहुंचे थे। टंकी का कवर हटाते ही जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया। इसके चलते वहां मौजूद डोलामणि सिदार (35), सुरेंद्र गुप्ता (28) अपधर मालाकार (40), पुरन्धन कुमार (21), अनिल कुमार (22), निमाणी भोय (40), रंजीत सिंह (34) बेहोश हो गए।

लॉकडाउन के चलते मिल बंद पड़ी थी

अभी तक मिली जानकारी अनुसार पेपर मिल में टंकी की सफाई करने के लिए 7 मजदूर गए थे। इसी दौरान गैस लीक होने लगी। इसकी चपेट में आने पर सभी मजदूर बेहोश होकर गिर पड़े। मिल के गार्ड ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया।

दखल

लॉकडाउन और जरूरत का पैमाना

शराब मानव जीवन और समाज में कैसी भी लाभदायक या नुकसानदेह भूमिका निभा रही हो, सरकार द्वारा लॉकडाउन में उसके ठेके खोलने का कदम राजस्व आय के सहायक के रूप में उसका उपयोग करने और लॉकडाउन के आर्थिक प्रभावों को थोड़ा कम करने के लिए उठाया गया है। इसके लिए यह भी ध्यान नहीं रखा गया कि इसके लतियों से मास्क और सुरक्षित दूरी के अनिवार्य प्रतिबंधों का पालन कैसे कराया जाएगा।

लॉकडाउन के पहले दो चरणों की समीक्षा व आमजन की जरूरतों को देखते हुए तीसरे चरण में कुछ रियायतें देने की आवश्यकता अनुभव हुई, तो सरकारों को खाने-पीने की और आवश्यक वस्तुओं के साथ शराब, तंबाकू और गुटखा जैसे पदार्थों की उपलब्धता की फिक्र भी सताने लगी। बिहार जैसे कई राज्यों की सरकारों ने इनको मानव जीवन के लिए न सिर्फ अनावश्यक, बल्कि हानिकारक मानते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। लेकिन 40 दिनों बाद लॉकडाउन के तीसरे चरण में इन्हें जनसामान्य को उपलब्ध करने की आवश्यकता अनुभव की गई और शराब के ठेकों सहित इनकी दुकानें खोल कर संचालित करने की ऐसी व्यवस्थाएं की गई, ताकि दो व्यक्तियों के बीच सुरक्षित दूरी का नियम और उसका पालन होता रहे। बिहार और महाराष्ट्र को छोड़ कर पूरे देश में इनके सुबह दस से शाम सात बजे तक संचालित रहने की अनुमति दी गई। इससे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही निकलता है कि संभवतः ये मानवीय जीवन की आवश्यकताओं में शामिल हैं, जिसके चलते इनकी सुलभता को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

इन ठेकों और दुकानों के खुलने से पहले ही उनके सामने लग गए खरीदारों के रेले से भी यही लगता है कि इनके बारे में लॉकडाउन लागू करते वक्त किया गया मूल्यांकन वास्तविकताओं पर आधारित नहीं था। देश के संविधान में शराब जैसी नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की भी चर्चा है। तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने सबसे पहले इस दिशा में कदम उठाए थे, लेकिन कुछ लोग इसे पीने को अपनी अनिवार्य आवश्यकता बता कर मामले को सर्वोच्च न्यायालय ले गए। वहां से निर्देश जारी हुआ कि उनकी अनिवार्यता को ध्यान में रख कर इसकी उपलब्धता के लिए परमिट प्रणाली शुरू की जाए, ताकि सरकारी एजेंसियों और डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार, जिनके लिए इन्हें आवश्यक माना गया है, वे इसे खरीदकर पी सकें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता तो क्या, दवा के रूप में भी शराब के सेवन को नकारते थे। गांधी जी के जो वारिस गांधीवादी समाज व्यवस्था बनाने का दावा करते थे, उन्होंने इस पर प्रतिबंध को संवैधानिक आवश्यकता समझ कर इसके लिए सत्ता की शक्तियों का प्रयोग भी किया।

वर्तमान स्थिति के मूल्यांकन के अनुसार इसकी सर्वस्वीकार्यता और अनिवार्यता स्वीकारने के बजाय ठेके और परमिट के आधार पर इसकी उपलब्धता की व्यवस्था की गई, जो फिलहाल केंद्र और राज्य सरकारों की आय का प्रमुख स्रोत है। पहले जो उत्पाद शुल्क इसके उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था, आज की तारीख में उस पर सरकारों की निर्भरता ही अनिवार्य-सी हो चली है। दूसरे पहलू पर जाएं तो मौजूदा परिस्थितियों में कोरोना महामारी से निपटने के लिए विभिन्न वर्गों व समुदायों पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनमें धार्मिक आस्थाओं व विश्वासों वाले पूजा-अर्चना के स्थानों पर भीड़ रोकने के लिए प्रतिबंध लगा कर उन्हें बंद भी किया गया। ऐसा प्रतिबंध शराब पर भी लगा, लेकिन उसमें अदालत द्वारा निर्णित श्रेणी में आने वालों को इसकी सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान नहीं था, उपलब्धता पर अंकुश ही लगाया गया था।

सवाल उठता है कि अब कोरोना महामारी से निपटने के राष्ट्रीय अभियान में तीसरे चरण की लॉकडाउन में प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हुए इस अंकुश को हटाने की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई, जबकि पिछले चरणों में नहीं अनुभव की गई थी? अभी पूर्णबंदी में जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की सर्वसुलभता के लिए जरूरी दुकानें भी पूरी तरह से खुलने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। नाइयों के हजामत बनाने जैसे व्यवसाय पर भी, जो उनकी जीविका का मुख्य स्रोत माना जाता है, अंकुश लगा हुआ है। ऐसे में यह कैसे कहा जा सकता है कि मध्य वर्ग की शराब की लत या आवश्कता ही शराब की दुकानें और ठेके खोलने के निर्णय के कारण बने? वास्तविकता तो यह है कि सरकारें शराब के ठेकों से होने वाले अपरिमित राजस्व लाभ के नुकसान को और लंबा नहीं खींचना चाहतीं, वरन उसकी उगाही कर लाभ उठाना चाहती थीं।

आंकड़े गवाह हैं कि लॉकडाउन के दौरान सरकारों की राजस्व आय बुरी तरह घट गई है और उनके पास इसे बढ़ाने का महज यही विकल्प है कि वे शराब के ठेके खोलें या पेट्रोलियम पदार्थों पर कर बढ़ाएं। इसलिए पूर्वोत्तर के एक राज्य ने दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम गिरने के दौर में भी उन पर पांच से साच रुपए ज्यादा कर का प्रावधान किया और कच्चे तेल के बाजार के अनुसार उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोलियम मूल्य निर्धारण का अनुपालन बंद कर दिया गया। निष्कर्ष स्पष्टतः यही है कि शराब मानव जीवन और समाज में कैसी भी लाभदायक या नुकसानदेह भूमिका निभा रही हो, सरकार द्वारा लॉकडाउन में उसके ठेके खोलने का कदम राजस्व आय के सहायक के रूप में उसका उपयोग करने और लॉकडाउन के आर्थिक प्रभावों को थोड़ा कम करने के लिए उठाया गया है। इसके लिए यह भी ध्यान नहीं रखा गया कि इसके लतियों से मास्क और सुरक्षित दूरी के अनिवार्य प्रतिबंधों का पालन कैसे कराया जाएगा। इसी कारण दिल्ली में कई जगहों पर सुरक्षित दूरी के उल्लंघन के चलते ठेकों को खुलते ही बंद कर देना पड़ा।

सवाल मौजूं है कि सरकार नशेड़ियों के लिए शराब की उपलब्धता की व्यवस्था में राजस्व लाभ के सिद्धांत को स्वीकृति देगी और राज्य संचालन में महामारी के दौर में भी इस प्रकार की प्रवृत्तियों को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करेगी, तो समाज में क्या, किस आदर्श का और कैसा नैतिक संदेश जाएगा? फिलहाल तो इसको अवसरवादी राजनीति के अंग के रूप में ही देखा जाएगा, जिसमें संकट की इस घड़ी में भी राज व्यवस्था की शक्तियों का प्रयोग सरकारी आमदनी बढ़ाने के ऐसे साधन के रूप में किया जा रहा है, जिसे न तो संविधान ने स्वीकारा है, न ही जीवन के आदर्शों के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से यह प्रश्न उठता है कि प्राथमिकताओं के आधार पर जनता के जीने और उसकी आवश्यकताओं या इनका निर्धारण सरकार को मिलने वाली अधिकतम आमदनी पर आधारित होगा। इसी रूप में जिन्हें नशीली वस्तुएं कहा जाता है, जिन पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए, अंकुश लग भी चुका है।

मध्य प्रदेश जैसे शराब बंदी वाले राज्य में नई दुकानें खुलवाने का निर्णय नई स्थितियों के लिए व्यवस्था बना कर और ठेके खोल कर ही संभव थी। यह कहा जा सकता है कि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट की दरों में भी वृद्धि की गई जो सकल सरकारी आय का लगभग तीस प्रतिशत की पूर्ति करते हैं। लेकिन मूल प्रश्न तो यही है कि राज्य और उसकी व्यवस्था भावी समाज का ऐसा स्वरूप बनाने के लक्ष्य पर निर्धारित होती है जिससे अधिकतम लोगों को लाभ हो सके और सामाजिक दृष्टि से जिसका प्रभाव व्यवस्था को उत्तम बनाने और ऐसा स्वरूप प्रदान करने वाला हो जो निर्धारित अपेक्षाओं के अनुकूल हो। लेकिन इस निर्णय से शराब की दुकानें पूरे देश में खोलने के निर्णय से यही लगता है कि अधिकतम लाभ की खोज में समाज को हम किस ओर ढकेलने जा रहे हैं।

विचार

कश्मीर में आतंक का खात्मा

आतंक का पर्याय बने हिज्बुल के टॉप कमांडर रियाज नायकू को एनकांउटर में ढेर कर दिया गया है। इसे हंदवाड़ा में भारतीय जवानों की शहादत का बदला माना जा रहा है। मगर जिस तरह से आतंकियों के हौसले बुलंद हैं, उसमें और सख्ती से पेश आना होगा।

कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में आतंकी घटनाओं में जिस तेजी से इजाफा हुआ है, वह चिंतित करने वाला है। यह तो अच्छा है कि आतंक का पर्याय बने हिज्बुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नायकू को एनकांउटर में ढेर कर दिया गया है। इसे हंदवाड़ा में भारतीय जवानों की शहादत का बदला माना जा रहा है। पुलवामा में जारी एनकाउंटर के बीच श्रीनगर में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इसके अलावा अवंतिपोरा के शरशाली खिरयू में भी दो आतंकियों को मार गिराया गया है। भारतीय सेना ने नायकू के सिर पर 12 लाख रुपए का इनाम रखा था। उसने घाटी में लंबे समय से दहशत फैला रखी थी। सब्जार बट की मौत के बाद रियाज को हिज्बुल का कमांडर बनाया गया था। बुरहान वानी के बाद वह घाटी में आतंक का नया पोस्टर बॉय बन गया था। रियाज बुरहान वानी के कोर ग्रुप का मेंबर था और बुरहान के मारे जाने के बाद उसे ही टॉप कमांडर बनाए जाने की चर्चा थी। पिछले साल उसने धमकी भरा ऑडियो जारी किया था। वीडियो में उसने घाटी में जेल स्टाफ पर हमले की धमकी दी थी।

बहरहाल, आए दिन सेना और सुरक्षाबलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ें बता रही हैं कि इनके नेटवर्क फिर से सक्रिय हो गए हैं और पहले की तरह हमलों को अंजाम देने में जुट गए हैं। रविवार को कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में ग्रामीण बंधकों को आतंकियों के चंगुल से छुड़ाने के दौरान सेना के एक कर्नल और एक मेजर सहित पांच जवान शहीद हो गए। पर संतोष की बात की यह है कि इन बहादुरों ने अपनी जान दांव पर लगा कर 11 बंधकों को बचा लिया था। जम्मू-कश्मीर में पिछले साल अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद यह उम्मीद बंधी थी कि आने वाले दिनों में घाटी में आतंकी गतिविधियां कमजोर पड़ेंगी। माना जा रहा था कि घाटी में जिस व्यापक स्तर पर सेना और सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ाई गई है, उससे आतंकियों के हौसले पस्त पड़ेंगे। कुछ समय ऐसा होता नजर आया भी और लगा कि आतंकी गतिविधियां बंद हो गई हैं। लेकिन सरकार ने जब से घाटी में पाबंदियों में ढील दी है, तब से आतंकी फिर से सिर उठाने लगे हैं। दरअसल, घाटी में सबसे बड़ी समस्या यह है कि आतंकी संगठनों ने गांव-गांव में अपनी जड़ें जमा ली हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सेना और सुरक्षाबलों के सघन तलाशी अभियान से आतंकी संगठनों के पसीने छूट रहे हैं। इसलिए वे अब जो हमले कर रहे हैं, वे हताशा का परिणाम ही हैं। आतंकी संगठन इस रणनीति पर चल रहे हैं कि हमलों से सेना व नागरिकों का मनोबल टूटेगा। अभी तक जितने ऐसे हमले हुए हैं, उनमें लश्कर और जैश के ही आतंकी ज्यादा निकले हैं। ऐसे में भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण इलाकों से आतंकियों का सफाया करने की है। जब तक गांवों से आतंकी नेटवर्क का खात्मा नहीं होगा, तब तक घाटी में शांति की उम्मीद नहीं की जी सकती।

आओ, अब बुद्ध हो जाएं

भारत ने महापुरुष होने की एकमात्र शर्त अभेद को बड़े समर्थ व व्यावहारिक ढंग से विश्व के सांस्कृतिक पटल पर स्थापित किया है। प्रत्येक महात्मा ने अपने ढंग और युगीन शैली के अनुरूप यह मार्ग प्रशस्त किया है। शंकर से अरविंद तक, कबीर से कलाम तक सब अभेद के एकमत से प्रस्तावक, समर्थक रहे। यही भारत में संतत्व का स्थापित आधार भी है। आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग इसी लौकिक अभेद भाव की अपेक्षा पर आश्रित है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यह पद भारत में सदियों से चर्चित और स्वीकृत रहा है। यद्यपि इस पद के पूर्व भी अभेद का भाव तो व्याप्त था ही। जितने भी ऋषि, मुनि, साधु संन्यासी, समाज सुधारक हुए उन सब का आप्त भाव प्राणिमात्र के प्रति अभेद ही रहा। इसी से वे उस स्थान पर हैं जहां वे पूज्य हैं, स्तुत्य हैं, सर्वस्वीकृत हैं, अनुकरणीय हैं। उन्होंने आचरण के मानक स्थापित किए उपदेश की पोथियां नहीं।

कोरे प्रवचनकार, उपदेशक या तकरीर कार कभी पूज्य या समाज के आदर्श नहीं हो पाए। उन्होंने शब्द तो खूब जाया किए पर भाव पात्र खाली ही रह गया। भाषा का तो विकास किया पर भाव सरिता सूखती ही गई। भाषा के शब्द, लय, वाक्य विन्यास, प्रभाव आदि में तो खूब उन्नति की पर कर्म क्षेत्र वीरान पड़ा रहा। उनके पास वक्तृता तो विलक्षण रही पर भाव में वह प्रभाव नहीं आ सका। जबकि महान विभूतियां विशाल भाव सागर हैं जिसमें आवेश और आवेग का स्खलन नहीं स्थिरता है। उनमें आधार है किसी विचार को, परंपरा को थामे रखने का। वे कूड़े करकट वाला सतही जल नहीं वे तो मुक्ता माणिक्य वाला गहरे पैठे हुआ नीर हैं। बुद्ध कभी उपदेशक नहीं रहे, पर उलटबांसी यह कि बुद्ध के उपदेश नाम से ढेर सारा साहित्य बिकता है और तमाम लोग भी बुद्ध पर उपदेश देते हैं। यह जानते हुए एक मौन आचरण हजारों उपदेशों से बड़ा है।

कुछ इस प्रकार आचरण की परंपरा विरल होकर भी समाज को हर देशकाल में राह दिखाती रही है, उनसे गुजरकर परंपरा भी परिष्कृत हो जाती है और कालांतर में यही उनका मत स्थापित होता है। इस परंपरा के सर्वाधिक प्रकाशित स्तंभों में से एक महात्मा बुद्ध हैं। उन्होंने किसी का खंडन कभी नहीं किया बस परिष्कार करते हैं वे। वे इतने अहिंसक हैं कि वैचारिक स्तर पर भी वे किसी को तोड़ते नहीं उसके विचारों में कुछ जोड़ते ही हैं। उनकी स्मिति मानों सदा सृजन का संदेश देती हो। भारत भूमि संतों की सुधारकों की भूमि रही है। संतत्व उपदेश देकर स्तुत्य नहीं होता वरन आचरण से अपनी भूमिका प्राप्त करता है। हम सदा से आचरण के पक्षधर रहे हैं। इसीलिए कोरा पढ़ना लिखना हमारी परंपरा में कभी स्वीकार नहीं हुआ। और तो और आचरण विहीन पढ़ाई निंदा का कारण जरूर बनी है। आचरण के जो मानदंड बुद्ध ने स्थापित किए उनका स्तर इतना था कि परवर्ती पुराणकारों ने भाष्यकारों ने बुद्ध को दशावतार में स्थान दिया।

आज बुद्ध जयंती है। ऐसे महात्मा का दिन, जिसने समाज और देश को वह राह दिखाई जो अनादि काल तक कायम रहेगी। सही मायने में बुद्धत्व एक अवस्था है। अवस्था जिसमें सब समभाव हों, अभिन्न भाव से भरे हों। उन्होंने भी कतिपय अपने बुद्धत्व को जागृत रखा। एकला चलो का आशय अकेले चलने भर से नहीं है, आज इसका यह अर्थ, कि एक होकर चलो, निकाला जाना श्रेयस्कर है।

यह चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए कि दशावतार में कौन है कौन नहीं। किस किस ग्रंथ ने बुद्ध को रखा किस किस ने छोड़ा। चर्चा इस पर होनी चाहिये कि जिसने भी बुद्ध को दशावतार में रखा, भले ही वह तथ्यात्मक रूप से सही हो या नहीं, उसके आधार क्या थे, वे कितने अनुकरणीय है। पर विडंबना यह है कि तमाम बौद्धानुयायी उनके पहनावे एयर वस्त्र तक ही सिमटे रह गए। कोई भी अवतार तब अवतार होता है जब वह समाज के, सृष्टि के, प्रकृति के व्यापक हितों को समझने लगे और उनके परिवर्द्धन की दिशा में प्रयास करने लगे। जब वह सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों ढंग से न्यायपूर्ण हो जाए। जब उसका आचरण संहिता बन जाए, जब वह निज से उठकर सबका हो जाये, जब वह विरोधियों को शत्रुओं को भी आत्मीयता से दुलार सके, जब वह अजातशत्रु हो जाये, जब वह सर्व मित्र हो जाए। वह बहुमत का नहीं सर्वकालिक सर्वमत की स्वीकृति का आधार बन जाए, तब कहीं जाकर काल उसकी गणना अवतारों में करता है। काल अपने पटल पर तब उन्हें अंकित करता है।

बुद्ध काल के पटल पर लिखी वही नवीनतम इबारत हैं। इसे महज संयोग कहा जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। बुद्ध ने तारीखों, तिथियों, सदियों और युगों को सार्थक किया है। बैशाख पूर्णिमा को उनका जन्म होना इस तिथि को भी सार्थक करता है। पूर्णिमा की शीतलता युक्त प्रकाश का वास्तविक संयोजन हम बुद्ध में बखूबी देख सकते हैं। यह गलतफहमी भी फैली या फैलाई गई कि बुद्ध किसी वर्ग विशेष के हैं, उनके मानने वाले विशेष ढंग से रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, केश सज्जा उनकी पहचान है। ऐसा मानने वाले सबसे बड़े नादान हैं। उनकी पहुंच मात्र बुद्ध के आवरण तक ही हो सकी। वे उनके आचरण तक 2600 वर्ष बाद भी नहीं पहुंच पाए। उन्होंने बुद्ध जैसी बहती हुई सरिता को रोक कर उसे सड़ाने का ही काम किया है। आज पानी सड़ कर दुर्गंध दे रहा है। बुद्ध को बांधा नहीं जा सकता, उनसा हुआ जा सकता है, उनमें बहा जा सकता है, उनमें उतरा जा सकता है। यह होना, बहना और उतारना ही बुद्ध की सच्ची साधना है। बुद्ध की सच्ची तस्वीर विश्व भर के प्रति अभिन्न करुणा मिश्रित आंखें देख सकती हैं। जब आपके विचारों से और आचरण से सब भेद तिरोहित हो जाएं तब समझिए आप बुद्ध में उतरने लगे हैं। यही बुद्धत्व को परखने का सूत्र है। हमारे घरों के ड्राइंग रूम में रखे मुखौटे या तस्वीरें बुद्ध नहीं हैं। उन्हें इन मुखौटों से बाहर निकालने का समय आ गया है। हमारा आचरण ही उनकी सच्ची प्रतिमा है। आओ इसी की पूजा करे। आओ इसी की शरण में चलें। आओ बुद्ध हों लें।

आज बुद्ध हमारे स्वागत कक्ष तक सिमट कर रह गए हैं, उन्हें यहां से निकल कर हृदय कक्ष तक ले जाना बहुत जरूरी है। दिखने में छोटी सी लगती यह दूरी बहुत लंबी है। आओ इसका प्रयास करें। आज 2600 वर्ष में बुद्ध मठों या स्वागत कक्षों से हमारे हृदय कक्ष तक नहीं पहुँच सके। बुद्ध जैसी सदा प्रवहमान भाव सरिता को सिद्धांतों के घाटों में मत बांधिए। उन्हें प्रतिमाओं से मुक्त करिए। यह कटु है पर सत्य है कि जितना नुकसान बुद्धत्व का उनके मतानुयायियों ने किया उतना तो उनके विरोधी भी न कर सके। बुद्धत्व तो एक अवस्था है। अवस्था जिसमें सब समभाव हों, अभिन्न भाव से भरे हों। आज गुरुदेव रवींद्रनाथ जयंती भी है। उन्होंने भी कतिपय अपने बुद्धत्व को जागृत रखा। एकला चलो का आशय महज अकेले चलने भर से नहीं है, आज इसका यह अर्थ, कि एक होकर चलो, निकाला जाना श्रेयस्कर है, प्रासंगिक है। वह अवस्था जब आप सबसे एक हो जाएं ही बुद्धत्व है। हर मनुष्य में बुद्धत्व कुछ न कुछ अंश में होता ही है। किसी में कम किसी मे ज्यादा।

जीवन है तो बुद्धत्व तो होगा ही। बुद्धत्व शून्य होना संभव नहीं। कुख्यात अंगुलीमाल में भी कुछ अंश था। अवतारों में यही गुण या फिर अवस्था अपने सर्वोत्तम रूप में होती है। यह कहना अतिश्योक्ति कतई नहीं होगी कि भगवान बुद्ध ने अवतारों की अवधारणा की नई व्याख्या विशुद्ध मानवीय आयामों में स्थापित की।

ट्विटर

जम्मू-कश्मीर में सेना को अपनी रणनीति बदलनी होगी। पाकिस्तान से आए आतंकियों को सेना के हर कदम का पता होता है, तभी वे अपने मंसूबे पूरे कर लेते हैं।

मारुफ रजा, रक्षा विशेषज्ञ

पाकिस्तान को सेना हर बार मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन वह सुधर नहीं रहा है। सेना जब तक उसे गहरे जख्म नहीं देगी, तब तक पड़ोसी में डर का भाव नहीं दिखेगा।

पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ

सत्यार्थ

प्रसन्नता की खोज

अंजन मुनि अपने आश्रम में अनेक शिष्यों को रखकर शिक्षा देते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा-आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि खुशी आसानी से किस तरह मिल सकती है? सभी शिष्य एक साथ बोले-गुरुजी, जल्दी बताइए। मुनि शिष्यों को एक कमरे में ले गए। वहां ढेर सारी एक जैसी पतंगें रखी हुई थीं। मुनि शिष्यों से बोले-इन पतंगों में से एक-एक उठाकर सभी अपना नाम लिखकर वापस वहीं रख दो। सभी ने एक-एक पतंग पर अपना नाम लिखा और वापस वहीं रख दीं। कुछ देर बाद

मुनि बोले-अब सभी अपने नाम की पतंग लेकर मेरे पास आओ। यह सुनकर शिष्यों में भगदड़ मच गई और अपने नाम की पतंग लेने के चक्कर में सारी पतंगें फट गईं। इसके बाद मुनि उन्हें दूसरे कमरे में ले गए। वहां भी ढेरों पतंगें थीं। उन्होंने सभी शिष्यों को एक-एक पतंग पर अपना नाम लिखने के लिए कहा। इसके बाद वे बोले-अब तुम सभी इनमें से कोई भी पतंग उठा लो। सभी शिष्यों ने बिना कोई जल्दबाजी किए आराम से एक-एक पतंग उठा ली। गुरुजी बोले-अब तुम एक-दूसरे से अपने नाम वाली पतंग प्राप्त कर लो। सभी शिष्यों ने बगैर खींचतान किए व बगैर पतंगें फाड़े अपने-अपने नाम की पतंग प्राप्त कर ली। गुरुजी बोले-हम खुशी की तलाश इधर-उधर करते हैं, जबकि हमारी खुशी दूसरों की खुशी में छिपी है। जब तुमने केवल अपने नाम की पतंग तलाशनी चाही, तो आपाधापी में सारी पतंगें फट गईं। दूसरी बार तुमने आराम से उठाकर दूसरे के नाम की पतंग उसे सौंप दी। इस तरह उसको भी खुशी मिल गई और तुम्हें भी अपने नाम की पतंग मिल गई। कहने का मतलब है कि असली खुशी दूसरों की मदद कर उन्हें खुशी देने से मिलती है।

न्यूज

कर्नाटक बैंक का शुद्ध लाभ 56 फीसदी घटा

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र के कर्नाटक बैंक का शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में 56 प्रतिशत घटकर 27.31 करोड़ रुपए रहा। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक ने 61.73 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि बीते वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 123.14 करोड़ रुपए रहा था। तिमाही के दौरान बैंक का प्रावधान और अन्य आकस्मिक खर्च बढ़कर 356.50 करोड़ रुपए हो गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 217.73 करोड़ रुपए था। तिमाही के दौरान बैंक की आय 18 प्रतिशत बढ़कर 2079.58 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1821.88 करोड़ रुपए थी। पूरे वित्त वर्ष 2019-20 में कर्नाटक बैंक का शुद्ध लाभ 9.5 प्रतिशत घटकर 431.78 करोड़ रुपए रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में 477.24 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष के दौरान बैंक की आय बढ़कर 7870.82 करोड़ रुपए हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 6907.92 करोड़ रुपए। संपत्ति के मोर्चे पर बात की जाए तो 31 मार्च, 2020 को बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां एनपीए बढ़कर कुल ऋण का 4.82 प्रतिशत हो गईं। एक साल पहले यह 4.41 प्रतिशत पर थीं।

यस बैंक के 18 हजार करोड़ के बांड की रेटिंग बरकरार

नई दिल्ली। क्रेडिट रेटिंग कंपनी क्रिसिल ने यस बैंक के 18000 करोड़ रुपए के बांड के लिये बीबीबी रेटिंग की फिर से पुष्टि की है। यस बैंक ने शेयर बाजारों को बताया कि क्रिसिल ने 13941 करोड़ रुपए के टियर-2 बांड तथा 3780 करोड़ रुपए के इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड की रेटिंग क्रिसिल बीबीबीस्टेबल बनाये रखने की पुष्टि की है। एजेंसी ने यस बैंक के जमा के प्रमाणपत्रों की रेटिंग को भी क्रिसिल ए2 बनाये रखा है। बीबीबी रेटिंग को वित्तीय देनदारियां पूरा करने के लिहाज से मध्यम सुरक्षा का माना जाता है। वहीं ए2 रेटिंग वाली ऋण प्रतिभूतियां बेहद सुरक्षित मानी जाती हैं। क्रिसिल ने इस बारे में कहा कि देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक की ठीक-ठाक हिस्सेदारी तथा प्रमुख शेयरधारकों से असाधारण संरचनात्मक समर्थन के कारण रेटिंग को पुराने स्तर पर बनाये रखा गया है।

ओपेक ने एक करोड़ बैरल प्रतिदिन कटौती को बढ़ाया

नई दिल्ली। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और उससे संबद्ध देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में करीब एक करोड़ बैरल प्रतिदिन की कटौती को जुलाई अंत तक एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है। यह कदम कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई स्थिति के मद्देनजर बाजार में स्थिरता लाने की उम्मीद में उठाया गया है। ओपेक से संबद्ध देशों और रूस की अगुवाई में इससे बाहर के देशों कीवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई बैठक में यह फैसला किया गया। इस कदम का मकसद अधिशेष उत्पादन को कम करना, कीमतों में आ रही गिरावट को थामना है। वैश्विक स्तर पर विमानन सेवाएं इस महामारी की वजह से अब भी लगभग ठप हैं, जिससे कच्चे तेल की मांग प्रभावित हुई है। उत्पादन में कुल कटौती वैश्विक स्तर पर आपूर्ति का करीब दस प्रतिशत बैठती है। हालांकि, कई देशों ने लॉकडाउन में अब ढील दी है लेकिन कच्चे तेल के बाजार में जोखिम कायम है। ओपेक के अध्यक्ष एवं अल्जीरिया के पेट्रोलियम मंत्री मोहम्मद अरकब ने चेताया कि इस साल के मध्य तक वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का भंडारण बढ़कर 1.5 अरब बैरल पर पहुंच जाएगा।

वाइल्डक्राफ्ट को एडिडास को पीछे छोड़ने की उम्मीद

नई दिल्ली। साहसिक यात्रा से जुड़े जरूरी सामान बैग इत्यादि बनाने वाली घरेलू कंपनी वाइल्डक्राफ्ट की योजना इस साल देश की सबसे बड़ी लाइफस्टाइल कंपनी बनने का है। भारतीय सेना से मिले ऑर्डर के बलबूते कंपनी को नाइकी, एडीडास, रीबोक और प्यूमा जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड को पीछे छोडने की उम्मीद है। कंपनी ने कहा कि भारतीय सेना को बैग और अन्य सामान की आपूर्ति के साथ अपने मौजूदा कारोबार से उसे इस साल 1000 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद है। कंपनी कोविड-19 के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देना चाहती है। कंपनी को सेना के ऑर्डर पूरे करने हैं, जो हमारे सबसे बड़े ऑर्डरों में से एक है। पिछले साल अंततः हमें भारतीय जवानों के लिए बैग की आपूर्ति करने का ऑर्डर मिल गया। हमने इस ठेके को हासिल किया और अब हम इसका उत्पादन करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने हाल ही में निजी सुरक्षा से जुड़े उत्पाद मसलन मास्क, निजी सुरक्षा किट इत्यादि के बाजार में प्रवेश किया है। कंपनी ने सुपरमास्क ब्रांड नाम से मास्क बाजार में उतारे हैं। हमारी नजर देश की सबसे बड़ी लाइफस्टाइल कंपनी बनने पर है।

निजी अस्पतालों पर कालाबाजारी का आरोप

हेल्थकेयर बाजार में निजी क्षेत्र की करीब 80 फीसदी हिस्सेदारी

नई दिल्ली। देश के हेल्थकेयर बाजार में प्राइवेट सेक्टर की करीब 80 फीसदी हिस्सेदारी है। देश के कुल हेल्थकेयर खर्च में उसकी 74 फीसदी हिस्सेदारी है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और निजी अस्पतालों पर बेड की कालाबाजारी के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर के कुछ निजी अस्पतालों पर बेड की कालाबाजारी का आरोप लगाया।

ऐसे में देश के बड़े अस्पतालों की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है। केजरीवाल ने कहा कि ज्यादातर अस्पताल बहुत अच्छे हैं, लेकिन दो-चार कालाबाजारी कर रहे हैं। हमने बीते मंगलवार को एप लॉन्च कर सारी जानकारी सार्वजनिक कर दी। फिर भी कुछ अस्पताल बदमाशी कर रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि बेड नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कुछ अस्पताल बेहद शक्तिशाली हैं, वे धमकी दे रहे हैं कि हम कोरोना के मरीज नहीं लेंगे। 2016 में भारत से हेल्थकेयर सेक्टर का आकार 110 अरब डॉलर था जिसके 2022 तक 372 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान इसके सालाना 22 फीसदी की चक्रवृद्धि दर से बढ़ने की उम्मीद है। भारत में हॉस्पिटल इंडस्ट्री 2017 में 61.79 अरब डॉलर की थी और 2023 तक इसके 132.84 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। देश के कुछ सूचीबद्ध नामी-गिरामी अस्पताल समूहों के हाल के प्रदर्शन पर एक नजर।

अपोलो समूह

अपोलो समूह देश का सबसे बड़ा अस्पताल समूह है। यह देश का पहला कॉरपोरेट हॉस्पिटल है जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसके देश-विदेश में 70 अस्पताल हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज ने पिछले कुछ सालों में 13 नए अस्पताल जोड़े हैं और इस पर करीब 2000 करोड़ रुपए निवेश किया है। साथ ही कंपनी देश में सबसे बड़ी रिटेल फार्मेसी चेन भी चलाती है। इसकी मौजूदगी 400 शहारों में है जो 20 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों में फैले हैं। अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पिछले साल की पहली तिमाही में दोगुना होकर 49.15 करोड़ रुपए हो गया था। स्वास्थ्य सेवाओं और दवा श्रेणी में मजबूत वृद्धि से मुनाफा बढ़ा। एक साल पहले की इसी तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 23.34 करोड़ रुपए था।

फोर्टिस हेल्थकेयर

फोर्टिस ब्रांड की स्थापना 1996 में हुई थी। फोर्टिस हेल्थकेयर देश की सबसे बड़ी हेल्थकेयर कंपनियों में से एक है। कंपनी अस्पतालों के अलावा डायग्नॉस्टिक्स और डे केयर स्पेशिएलिटी फैसिलिटी भी चलाती है। इसके भारत, दुबई और श्रीलंका में 36 अस्पताल हैं। पिछले साल कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 78.01 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी ने इस दौरान अस्पताल और नैदानिक कारोबार में अच्छी वृद्धि हासिल की है। एक साल पहले इसी तिमाही में उसे 52.80 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।

एस्टर डीएम हेल्थकेयर

एस्टर डीएम हेल्थकेयर, जो भारत के कई राज्यों में सबसे बड़े प्राइवेट हेल्थकेयर सेवा प्रदाताओं में से एक है। कंपनी भारत सहित नौ देशों में मौजूद 24 अस्पतालों, 114 क्लिनिक और 219 से अधिक फार्मेसी चलाती है। कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त पूरे वर्ष के लिए 355 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज कराया।

नारायण हृदयालय लिमिटेड

इस कंपनी का मुख्यालय बेंगलूरु में है और देशभर में इसके अस्पताल हैं। खासकर कर्नाटक और पूर्वी भारत में कंपनी कई अस्पताल चलाती है। साथ ही कंपनी उत्तरी और पश्चिमी में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है। पिछले साल सितंबर तिमाही में कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 45.3 करोड़ रुपए रहा।

शेयर समीक्षा : कंपनियों के तिमाही नतीजों पर भी रहेगी निवेशकों की निगाह

शेयर बाजार में मजबूती जारी रहने की आस

मुंबई । देश में आर्थिक गतिविधियां शुरू होने के बाद पिछले सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में करीब छह फीसदी की मजबूती रही तथा आने वाले सप्ताह में भी तेजी का क्रम जारी रहने की उम्मीद है। कारोबारियों ने बताया कि आर्थिक गतिविधियां शुरू होने से अर्थव्यवस्था को लेकर निवेशकों में विश्वास दुबारा बहाल हुआ है। इसका असर आने वाले सप्ताह में भी जारी रहेगा।

दूसरे देश भी धीरे-धीरे प्रतिबंधों में ढील दे रहे हैं। इस कारण विदेशों से भी लगातार सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। आगामी सप्ताह शुक्रवार को मई की खुदरा महंगाई और अप्रैल के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े जारी होने हैं। इन पर भी निवेशकों की नजर होगी। इनके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भेल के वित्तीय परिणाम भी जारी होंगे। कंपनियों के तिमाही नतीजों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों और रुपए की चाल भी शेयर बाजार की गति को प्रभाति करेगी। साथ ही विदेशी निवेशकों एफपीआई और घरेलू निवेशकों का मूड भी शेयर बाजार की चाल को प्रभावित करेगा। सरकार ने एक जून से लॉकडाउन के बीच लगभग सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दे दी है। इससे लगातार दूसरे सप्ताह शेयर बाजारों ने ऊंची उड़ान भरी। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1,863.14 अंक यानी 5.75 प्रतिशत चढ़कर सप्ताहांत पर 34,287.24 अंक पर बंद हुआ जो 11 मार्च के बाद का उच्चतम स्तर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 5.86 फीसदी की साप्ताहिक बढ़त में 10,142.15 अंक पर पहुंच गया।

एफपीआई का जून के पहले सप्ताह में 18589 करोड़ रुपए निवेश

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने जून के पहले सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजारों में 18589 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन में ढील से बाजार धारणा सुधरने से विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजारों के प्रति भरोसा बढ़ा है। इसके अलावा सप्ताह के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज का बड़ा राइट्स इश्यू बंद हुआ है। इसे अधिक अभिदान मिला है। साथ ही उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक में 2.8 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है जिससे विदेशी निवेशकों का प्रवाह बढ़ा है। जून के पहले पांच कारोबारी सत्रों यानी एक से पांच जून के दौरान एफपीआई ने शेयरों में 20814 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस दौरान उन्होंने ऋण या बांड बाजार से 2225 करोड़ रुपए की निकासी की। इस तरह उनका शुद्ध निवेश 18589 करोड़ रुपए रहा। इससे पहले विदेशी निवेशक लगातार तीन महीने बिकवाल बन रहे। उन्होंने मई में 7366 करोड़ रुपए, अप्रैल में 15403 करोड़ रुपए और मार्च में रिकॉर्ड 1.1 लाख करोड़ रुपए की निकासी की थी।

भारत पर दांव लगाने का शानदार मौका

गौतम अडाणी ने माना, फिलहाल स्थिति गंभीर

नई दिल्ली। कोरोना के कारण देश की इकॉनामी पर काफी बुरा असर हुआ है। मूडीज ने तो रेटिंग भी घटा दी है, जिसके बाद निवेशकों के मन में सवाल खड़ा होना लाजिमी है। हालांकि उद्योगपति गौतम अडाणी कहना है कि भारत पर दांव लगाने का इससे अच्छा समय नहीं आएगा।

उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि दर में हालिया गिरावट के बावजूद भारत दुनिया का प्रमुख उपभोग केंद्र होगा। साथ ही अगले कई दशक तक भारत दुनिया का विनिर्माण और सेवाओं का प्रमुख केंद्र रहेगा। बीते वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 4.2 प्रतिशत पर आ गई है, जो इसका करीब एक दशक का निचला स्तर है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक का भी अनुमान है कि कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के चलते चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट आएगी। अडाणी गैस लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट में अडाणी ने कहा, हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी विचार पूरी तरह सही या गलत नहीं हो सकता। आज इस संकट के समय जरूरत ऐसी सरकार की है जो उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर निर्णय ले सके। साथ ही नई सूचनाएं आने पर खुद को उसके अनुकूल ढाल सके। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से पैदा हुए संकट के बीच भारत ने अच्छा काम किया है। वहीं अधिक संसाधनों वाले देशों को संघर्ष करना पड़ा है। अडाणी ने कहा कि इस वायरस से लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जो फैसले लिए गए हैं, यदि उनमें विलंब होता, तो आज हमारे सामने बड़ी आपदा खड़ी हो जाती, जिसका न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया पर असर पड़ता।

म्यूचुअल फंड योजनाओं ने दिया 25 फीसदी रिटर्न

रिजर्व बैंक के तरलता उपायों से मिला अधिक फायदा

नई दिल्ली। शेयर आधारित म्यूचुअल फंड योजनाओं ने व्यापक बाजार में सुधार के बीच लॉकडाउन के दौरान 25 प्रतिशत का प्रतिफल रिटर्न दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि रिजर्व बैंक के तरलता उपायों तथा सरकार द्वारा प्रोत्साहनों की घोषणा से भी म्यूचुअल फंड अधिक रिटर्न दे पाए।

हालांकि, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह मंदड़िया आधारित तेजी से अधिक कुछ नहीं है। प्राइम इन्वेस्टर डॉटइन ने कहा किम्यूचुअल फंड हालांकि मार्च के निचले स्तर से उबर गए हैं लेकिन दीर्घावधि का रिटर्न अब भी खराब रहने का अनुमान है। मॉर्निंगस्टार इंडिया द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार सभी इक्विटी योजना श्रेणियों इक्विटी से जुड़ी बचत योजना ईएलएसएस, मिडकैप, लार्ज और मिडकैप, लार्जकैप, स्मॉलकैप, मिडकैप और मल्टीकैप ने 25 मार्च से तीन जून के दौरान 23 से 25 प्रतिशत का रिटर्न दिया। अलग-अलग देखा जाए तो लार्ज कैप कोषों ने 25.1 प्रतिशत का रिटर्न दिया।

बंदरगाहों पर कार्गो 22 फीसदी घटकर 9.3 करोड़ टन

नई दिल्ली । लॉकडाउन से देश के प्रमुख बंदरगाहों पर माल को चढ़ाने-उतारने में भारी गिरावट आई है। उद्योग के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहले दो माह अप्रैल-मई में प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो का रखरखाव 22 प्रतिशत घटकर 9.28 करोड़ टन रह गया।

भारतीय बंदरगाह संघ आईपीए के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इन 12 प्रमुख बंदरगाहों ने पिछले वित्त वर्ष के पहले दो माह में 11.92 करोड़ टन माल चढ़ाया और उतारा था। अप्रैल-मई में चेन्नई, कोचिन और कामराजार जैसे बंदरगाहों पर कार्गो में 40 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। वहीं कोलकाता व जेएनपीटी में 30 प्रतिशत से अधिक की कमी आई। देश में केंद्र सरकार के तहत आने वाले 12 प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल पूर्व में कांडला, मुंबई, जेएनपीटी, मोरमुगाओ, न्यू मेंगलूर, कोचिन, चेन्नई, कामराजार पूर्व में एन्नोर वीओ चिदंबरनार, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता हल्दिया सहित हैं। इन बंदरगाहों ने पिछले वित्त वर्ष में 70.5 करोड़ टन माल चढ़ाया और उतारा था। आंकड़ों के अनुसार कामराजार बंदरगाह पर कार्गो में अप्रैल-मई में 46 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 32.2 लाख टन रहा।

कोयला आयात 20 फीसदी गिरा

मई में घटकर 1.9 करोड़ टन रहा

नई दिल्ली। मांग में नरमी के बीच देश में कोयले का आयात मई माह में सालाना आधार पर 20 प्रतिशत गिरकर 1.89 करोड़ टन रहा। यह जानकारी एमजंक्शन की ताजा रपट से मिली है। एमजंक्शन टाटा स्टील और सेल की संयुक्त उद्यम कंपनी है जो कंपनियों के बीच ऑनलाइन खरीद-फरोख्त का मंच उपलब्ध कराती है। यह कोयला और स्टील कारोबार पर अध्ययनपरक रपटें भी जारी करती है।

मई 2020 में आयात किए गए कोयले में 1.32 करोड़ टन गैर कोकिंग कोयला था। सरकार देश में कोयले के आयात पर निर्भरता 2023-24 तक शून्य करने की योजना पर कार्य कर रही है। फिलहाल कुछ समय तक आयातित कोयले की मांग नरम रहने का अनुमान है। इस समय देश में कोयला खदानों और बिजलीघरों पर कोयले का काफी स्टॉक पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल मई में कोयला आयात 2.35 करोड़ टन था। रपट के अनुसार इस बार मई में एक माह पहले के 1.70 करोड़ टन की तुलना में कोयला आयात 10.76 प्रतिशत सुधरा है। कोविड-19 के चलते देश भर में आवागमन पर लगी पाबंदियों के चलते आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक बंद थीं। इसका असर कोयले के आयात पर भी पड़ा। मई में गतिविधियों में थोड़ा बहुत ढील दी गयी।

जियो को मिला सातवां निवेशक

नई दिल्ली। मुकेश अंबानी को रिलायंस जियो का सातवां निवेशक मिल गया। अबू धाबी इंवेस्टमेंट अथारिटी एडीआईए जियो प्लैटफॉर्म्स में 5683 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। पिछले सात सप्ताह में जियो में अब तक कुल 97885 करोड़ रुपए निवेश किए जा चुके हैं। अबू धाबी इंवेस्टमेंट अथारिटी ने जियो की इक्विटी वैल्यू 4.91 लाख करोड़ और एंटरप्राइजेज वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रुपए आंकी है। इस निवेश के साथ एडीआईए का जियो में हिस्सेदारी 1.16 फीसदी होगी। जियो में निवेश की शुरुआत फेसबुक ने की थी। उसने करीब 44 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया था और 9.99 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी। उसके बाद सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, केकेआर, मुबाडला और अब एडीआईए ने सातवें निवेशक के रूप में निवेश किया है।

आरसीएफके औद्योगिक उत्पाद बिक्री 100 करोड़ पार

नई दिल्ली। कोविड-19 संकट के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स आरसीएफ के औद्योगिक उत्पादों की बिक्री का आंकड़ा चालू वित्त वर्ष के पहले दो माह में 100 करोड़ रुपए को पार कर गया है। उर्वरक मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा, कंपनी का परिचालन सफलतापूर्वक चल रहा है। कोविड-19 के मौजूदा संकट के दौर में कंपनी चुनौतियों से निपटने को पूरी तरह तैयार है। साथ ही कंपनी सामने आने वाले अवसरों का लाभ उठाने को भी तैयार है। आरसीएफ के प्रमुख उत्पादों में अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम बाई-कार्बोनेट, मिथाइल अमाइंस, नाइट्रिक एसिड, डिल्यूट नाइट्रिक एसिड, आर्गन फॉर्मिक एसिड, डि-मिथइल फार्माइड, डि-मिथाइल एक्टामाइड और सोडियम नाइट्रेट शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि आरसीएफ का एकल शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष 2019-20 में 49 प्रतिशत बढ़कर 208.15 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 139.17 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की परिचालन आय 9698 करोड़ रुपए रही। यह कंपनी के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है।

हवाई यात्रियों की संख्या 65 हजार के पार

नई दिल्ली। नियमित घरेलू यात्री विमान सेवा 25 मई को दोबारा शुरू होने के बाद से शनिवार को पहली बार 65 हजार से अधिक यात्रियों ने इनमें सफर किया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को बताया कि दुबारा उड़ानें शुरू होने के बाद 13वें दिन 06 जून को 674 उड़ानों में 65,080 यात्री अपने गंतव्य तक पहुँचे। एक दिन पहले की तुलना में हालाँकि उड़ानों की संख्या कम रही, लेकिन यात्रियों की संख्या बढ़कर पिछले 13 दिन में पहली बार 65 हजार के पार पहुँची है। इससे पहले पांच जून को कुल 697 उड़ानें रवाना हुईं जिनमें 64,500 यात्री अपने गंतव्य तक पहुँचे थे जबकि एक जून को 692 उड़ानों में 64,651 यात्रियों ने सफर किया था। कोविड-19 महामारी का संक्रमण नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 25 मार्च से देश में घरेलू उड़ानों के परिचालन पर रोक लगा दी थी। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन 22 मार्च से ही बंद है। केंद्र सरकार ने नये दिशा-निर्देशों के साथ 25 मई से एक-तिहाई घरेलू यात्री उड़ानों के परिचालन की अनुमति दी है।

2019-20 में मंद रहा प्रत्यक्ष कर संग्रह

4.92 प्रतिशत गिरकर 12.33 लाख करोड़ रुपए

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2019-20 में वास्तविक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 4.92 प्रतिशत गिरकर 12.33 लाख करोड़ रुपए रहा। इसकी प्रमुख वजह कॉरपोरेट कर की दरों में कटौती, मानक कटौती और व्यक्तिगत आयकर की छूट की सीमा बढ़ाया जाना है।

आयकर विभाग ने रविवार को कहा कि यदि व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट आयकर को पुरानी दरों से वसूला जाता तो 2019-20 के दौरान सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह के आठ प्रतिशत बढ़कर 14.1 लाख करोड़ रुपए हो सकता था। वित्त वर्ष 2018-19 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 1297674 करोड़ रुपए था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा, यह एक वास्तविकता है कि 2019-20 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 2018-19 के मुकाबले कम रहा। लेकिन इसकी अनुमान पहले से था। इसकी प्रमुख वजह 2019-20 के दौरान ऐतिहासिक कर सुधार करना है जिसके चलते ज्यादा रिफंड जारी किए गए।

वित्त वर्ष 2019-20 में वास्तविक कॉरपोरेट कर संग्रह 6.78 लाख करोड़ रुपए और व्यक्तिगत आयकर संग्रह 5.55 लाख करोड़ रु रहा। इस प्रकार 2019 -20 के लिए वास्तविक कर संग्रह 1233720 करोड़ रु रहा। वित्त वर्ष के दौरान कॉरपोरेट कर की दर में कटौती से 1.45 लाख करोड़ रु कर संग्रह में कमी आयी। वहीं व्यक्तिगत आयकर सीमा पांच लाख रु तक बढ़ाने व मानक कटौती की सीमा 50000 रु तक बढ़ाने से भी 23200 करोड़ रुपए का कर संग्रह कम हुआ।

1.84 लाख करोड़ रुपए के कर रिफंड जारी

वित्त वर्ष 2019-20 में सीबीडीटी ने 1.84 लाख करोड़ रुपए के कर रिफंड जारी किए। यह 2018-19 के 1.61 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 14 प्रतिशत अधिक है। सरकर ने पिछले साल सितंबर में किसी तरह की कर छूट इस्तेमाल नहीं करने वाली सभी घरेलू कंपनियों के लिए कर की दर घटाकर 22 प्रतिशत कर दी थी। इस तरह की कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट के भुगतान से भी राहत दी गयी थी। वहीं किसी विशेष कर छूट का लाभ नहीं लेने वाली नयी घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए कर की दर घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गयी थी।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा पावरकॉम को 8 मई से राज्य भर में सभी 515 कैश काऊंटर खोलने के आदेश

उपभोक्ताओं के बिल भरने के लिए प्रात:काल 9 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे काऊंटर

चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.) को 8 मई से राज्य भर में प्रात:काल 9 बजे के बाद दोपहर 2 बजे तक सभी 515 कैश क्लैकशन सैंटर उपभोक्ताओं के बिल जमा करवाने के लिए चलाने के आदेश दिए और स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों की सख्ती से पालना को यकीनी बनाने के लिए कहा। राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स की सिफारशों के आधार पर पी.एस.पी.सी.एल. की तरफ से काम शुरू के लिए तैयार की विस्तृत रणनीति को मंजूरी देते हुये कैप्टन अमरिन्दर सिंह जिनके पास बिजली का विभाग भी है, ने मीटर रीडरों को मीटरों पर इकाईयों के उपभोग संबंधी सूचना एकत्रित करने (मीटर रीडिंग) का कार्य बहाल करने के लिए कहा जिससे बिजली बिलों संबंधी शिकायतों की संख्या घटाने के लिए उपभोक्ताओं को यूनिटों के उपभोग के अनुकूल बिल देना यकीनी बनाया जा सके।

सभी मीटर रीडरों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी कायम करने के लिए कहा गया है। इसी दौरान कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने दोषपूर्ण मीटरों को बदलने के अलावा ज़रूरत के मुताबिक मीटर और ज़रूरी सामान की पूर्ति के लिए स्टोरों और मीटरिंग लैबों समेत अन्य सरगर्मियां शुरू करने की भी मंजूरी दे दी। इस तरह दोषपूर्ण मीटरों को बदलने से इसके बारे में शिकायतों में कमी आयेगी। इसके अलावा वितरण विभागों (डी.एस. /एपीडीआरपी /टीएस /पी.एंड एम) की तरफ से निर्माण और रख -रखाव सम्बन्धी सभी गतिविधियां भी फिर से शुरू की जाएंगी जैसे गर्मियों और धान की बुआई के लिए तैयारियाँ और उपभोक्ताओं के लिए निर्विघ्न बिजली सप्लाई सम्बन्धी अग्रिम योजनाबंदी करना शामिल है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से प्रमुख सचिव बिजली श्री ए.वेणू प्रसाद को सभी डिप्टी कमीशनरों और ज़िला पुलिस मुखियों के लिए हिदायतें जारी करने के निर्देश दिए गए जिससे पावरकॉम को इन गतिविधियों को सुचारू रूप में अमल में लाने के लिए अपेक्षित सहायता और सहयोग मिल सके। कानून को लागू करने वाली एजेंसियों से स्थानीय स्तर पर सहयोग मुहैया करवाए जाने के लिए भी कहा गया जिससे कैश काऊंटरों पर भीड़ जमा होने से रोका जा सके। यहाँ यह ज़िक्रयोग्य है कि राज्य सरकार की तरफ से लोगों के यातायात, दफ्तरों और अदारों को खोले जाने सम्बन्धी हिदायतें जारी की जा चुकी हैं जिससे कोविड -19 की महामारी को फैलने से रोका जा सके।

राजनैतिक दखलअंदाज़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता, कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी के खिलाफ केस संबंधी कहा

कानून अपना काम करेगा और पुलिस पूरी गहराई में निष्पक्ष जांच करेगी

चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने गुरूवार को पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी की तरफ से अपने ख़िलाफ़ 1991 के एक अगवा केस में एफ.आई.आर. दर्ज होने को राजनैतिक हितों से प्रेरित होने के लगाऐ दोषों को सिरे से रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनैतिक दखलअन्दाज़ी का सवाल ही नहीं पैदा होता और कानून इस मामले में अपना काम करेगा। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि सुमेध सैनी के ख़िलाफ़ केस बलवंत सिंह मुलतानी की गुमशुदगी का है जो पूरी तरह पीड़ित के भाई पलविन्दर सिंह मुलतानी निवासी जालंधर की तरफ से पाई ताज़ा आवेदन पर आधारित है। पलविन्दर मुलतानी की शिकायत पर मोहाली में बुधवार को धारा 364 (कत्ल के इरादे से अगवा करने), 201 (सबूत को गायब करना), 344 (ग़ैर कानूनी हिरासत में रखना) 330 (दबाव बना कर इकबालिया बयान लेना) और 120 -बी (अपराधिक साज़िस रचना) के अंतर्गत केस दर्ज किया गया। पुलिस को मंगलवार को ताज़ा शिकायत मिली थी। प्रवक्ता ने खुलासा करते हुये कहा कि शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के 7 दिसंबर, 2011 को आदेशों के पैरा 80 का हवाला दिया, 'जिस आवेदक ने सी.आर.पी.सी. की धारा 482 के अंतर्गत याचिका दाख़िल की है, ताज़ा कार्यवाही करवा सकता अगर कानून में इजाज़त है।'

शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि मुलजिम व्यक्तियों की गैर-कानूनी कार्यवाहियों स्पष्ट तौर पर सोच समझ कर अपराध किये जाने का खुलासा करती हैं जैसे कि सी.बी.आई. ने प्राथमिक जांच में साबित किया है और इसलिए यह पुलिस की गंभीर ज़िम्मेदारी बनती है कि वह 'ललिता कुमारी बनाम यू.पी. स्टेट और अन्य रा%यों के मामले' में सुप्रीम कोर्ट के विशेष दिशा निर्देशों के अनुसार मुलजिमों के विरुद्ध इन घिनौनी कार्रवाईयों के लिए केस दर्ज करे। पलविन्दर मुलतानी ने अपनी शिकायत में कहा कि बलवंत मुलतानी को 11 दिसंबर, 1991 को मोहाली में उस समय उसकी रिहायश से उठा लिया गया था और उस समय पर एस.एस.पी. चंडीगढ़ सुमेध सिंह सैनी पुत्र रोमेश चंद्र सैनी के आदेशों पर सैक्टर 17 चंडीगढ़ में थाने ले जाया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा, 'सुमेध सिंह सैनी की दहशत और प्रभाव के कारण उसकी रिहाई के लिए की गई सभी कोशिशों के बावजूद परिवार उसे वापस लाने में असफल रहा।' शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि सैनी की सेवा मुक्ति के बाद उन्होंने इंसाफ़ की लड़ाई के लिए अपनी कोशिशें फिर शुरू करने की हिम्मत जुटायी। उनके निरंतर यत्नों के परिणामस्वरूप आखिरकार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के अंतर्गत एक प्राथमिक जांच की गई जिसके बाद सी.बी.आई. चंडीगढ़ के द्वारा आई.पी.सी. की धारा 120 (बी), 364, 343, 330, 167 और 193 के अंतर्गत एफआईआर नंबर आर.सी 512008(एस) 0010 तारीख़ 02 -07 -2008दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसने हाई कोर्ट के आदेशों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि हाई कोर्ट के बैंच के पास इस केस का निपटारा करने के लिए अधिकार क्षेत्र की कमी है और नतीजे के तौर पर सी.बी.आई. की तरफ से इन आदेशों के आधार पर दर्ज एफ.आई.आर. को सिर्फ़ तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया गया था।

न्यूज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने गुरु अमरदास साहिब के प्रकाशोत्सव पर दी बधाई

भोपाल, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरू अमरदास जी साहिब के प्रकाशोत्सव पर हार्दिक बधाई प्रेषित की है। श्री चौहान ने ट्वीट कर कहा 'रुद्र धिआन गिआन सतिगुर के कबि जन भल्य उनह जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहि बनि आवै। सामाजिक सौहार्द व मानवता के कल्याण के लिए अपने सम्पूर्ण जीवन को समर्पित कर देने वाले, गुरु अमरदास जी साहिब के प्रकाशोत्सव की हार्दिक बधाई। आपकी कृपा हो, जगत का कल्याण हो, यही प्रार्थना।'

जाधव मामले में आईसीजे के फैसले को लेकर पाकिस्तान के संपर्क में भारत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने को लेकर भारत पाक के संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को अप्रैल 2017 में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। बाद में भारत जाधव तक राजनयिक पहुंच प्रदान करने से इनकार करने और मौत की सजा को चुनौती देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे पहुंचा। पिछले साल 17 जुलाई को इस मामले में अपने फैसले में आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव की सजा की प्रभावी समीक्षा करने का आदेश दिया और बिना किसी देरी के उन्हें राजनयिक पहुंच प्रदान करने को कहा। सूत्रों के अनुसार आईसीजे के फैसले को लागू करने के लिए भारत राजनयिक माध्यमों से पाकिस्तान के संपर्क में है।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, पूरी तरह सुरक्षित है आरोग्य सेतु एप

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक कार्यालय जाने वाले हर सरकारी व निजी कर्मचारी के फोन में आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप से इंस्टॉल होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सतत इस एप का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। देश में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लांच किए गए मोबाइल एप आरोग्य सेतु पर विपक्ष के सवालों और आरोपों को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निराधार बताया है। केंद्रीय आईटी मंत्री प्रसाद ने कहा कि यह एप डाटा और निजता की सुरक्षा के मामले में बहुत मजबूत है। यह भारत का तकनीकी अविष्कार है और कोविड-19 से लड़ने में कारगर है। बता दें कि मंगलवार को फ्रांस के एक हैकर और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इलियट एल्डर्सन ने दावा किया था कि एप की सुरक्षा में खामी पाई गई है। दावा किया था कि आरोग्य सेतु एप की सुरक्षा में खामी पाई गई है और कहा था कि नौ करोड़ भारतीय नागरिकों की निजता खतरे में है। इस दावे को खारिज करते हुए भारत सरकार ने कहा था कि एथिकल हैकर द्वारा किसी भी उपयोगकर्ता की जानकारी खतरे में होने की बात नहीं कही गई है।

पॉजिटिव मरीजों की पहचान सार्वजनिक करने पर होगी कार्रवाई : उपायुक्त

दुमका, (एजेंसी)। झारखंड के दुमका जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया एवं अन्य सूचना माध्यमों से कोराना वायरस (कोविड 19) के पॉजिटिव मरीजों की पहचान को सार्वजनिक करने पर विधिसम्मत कार्रवाई किऐ जाने की सख्त हिदायत दी है। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने बुधवार को कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जिले में दो कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। इसी क्रम में उन्होंने सभी प्रिंट मीडिया, इलेट्रॉनिक मीडिया, फेसबुक, ट्स्एप, ट्वीटर आदि सोशल मीडिया के एडमिन एवं आमजनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान एवं परिजनों की तस्वीर आदि से संबंधित जानकारी प्रकाशित नहीं करने की हिदायत देते हुए कहा कि मरीज से संबंधित कोई भी सूचना माध्यमों से किसी प्रकार की सूचना किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक नहीं किया जाये। श्री राजेश्वरी ने कहा कि ऐसा करते पाये जाने पर संबंधित लोगों को चिन्हित कर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

भागलपुर में पुलिस थाने पर हमला करने के मामले में तीन गिरफ्तार

भागलपुर (एजेंसी)। बिहार में भागलपुर जिले के ईशीपीर बाराहाट थाने पर हमला करने और पुलिस कर्मियों पर पथराव करने के मामले में दो वार्ड सदस्यों समेत तीन लोगों को बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने यहां बताया कि मामले में बारा पंचायत के दो वार्ड सदस्य पंकज कुमार दास और जयप्रकाश रविदास के अलावा एक आरोपी विश्वनाथ दास को विभिन्न ठिकानों से छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि नामजद आरोपियों को कड़ी पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। श्री भारती ने बताया कि इस मामले में नामजद 21 फरार उपद्रवियों के धरपकड़ के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और बहुत जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ईशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र के बारा महादलित गांव में कुछ दिन पूर्व लॉकडाउन का उल्लंघन कर सड़क पर एकत्र भीड़ को समझाने गई पुलिस गश्ती दल पर उपद्रवियों ने पहले पथराव किया और फिर थाने पर हमला कर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था। इस पथराव में सब इस्पेक्टर जितेन्द्र पासवान सहित कई पुलिस कर्मी जख्मी हो गए थे। श्री पासवान के बयान पर 25 नामजद समेत पचास अज्ञात उपद्रवियों के विरुद्ध एक प्राथमिकी संबंधित थाना में दर्ज की थी।

प्रदेश में कोरोना के मद्देनजर रेरा ने दी रियल एस्टेट सेक्टर को राहत

पंजीकृत परियोजनाओं को दी छह माह की छूट

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने कोरोना महामारी के कारण रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़े विपरीत प्रभाव को देखते हुए राहत देने का निर्णय लिया है। इसके मद्देनजर पंजीकृत परियोजनाओं को पंजीयन अवधि में गत 15 मार्च से छह माह की छूट प्रदान की है। बिल्डर तथा ऐजेंट को रिटर्न जमा करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ाई गई है। प्राधिकरण के इस निर्णय से प्रदेश की पंजीकृत करीब 3000 परियोजनाओं को लाभ मिलेगा। प्राधिकरण का यह निर्णय रियल एस्टेट सेक्टर को पुनर्जीवित करने मे भी सहायक होगा।

रिटर्न जमा करने की तारीख 30 जून तक बढ़ाई

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गत 19 फरवरी को कोरोना त्रासदी को फोर्स मेज्योर की श्रेणी मे रखा गया है। साथ ही उद्योगों को इसके प्रभाव से निपटने के लिए अनेक राहत एवं छूट प्रदान की गई है। रिर्जव बैंक ने भी सभी बैंको को उनके द्वारा प्रदाय निश्चित अवधि के ऋण तथा मासिक ईएमआई के भुगतान पर भी तीन महीने की मोहलत देने की अनुमति दी है। आवासीय एवं नगरीय विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन गठित केन्द्रीय सलाहकार समिति ने भी कोरोना त्रासदी के मद्देनजर प्रोजेक्ट के पंजीकृत को 6 माह का विस्तार देने की अनुंशसा की है। इस संबंध में सम्प्रवर्तकों की अनेक संस्थाओं ने भी प्राधिकरण को राहत देने के लिए अभ्यावेदन दिये थे। प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि जिन परियोजनाओं की पूर्णता गत 15 मार्च और उसके बाद होनी थी उनका पंजीयन, समाप्ति दिनांक से छह माह के लिए बढाया जायें। रेरा में जिन परियोजनाओं के पंजीयन में विस्तार संबंधी आवेदन विचारधीन हैं, उनकी पंजीयन अवधि में छह माह का अतिरिक्त विस्तार निःशुल्क दिया जाये। साथ ही जिनके पंजीयन गत 15 मार्च के पहले समाप्त हो गये थे एवं जिनके द्वारा अभी तक विस्तार के लिये प्राधिकरण में आवेदन नही किया गया है, ऐसी परियोजनाओं द्वारा विस्तार चाहे जाने पर उनकी अंतिम वैधता अवधि में भी छह माह का विस्तार अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाए।

सम्प्रवर्तक एवं ऐजेंट को जो वैधानिक आवश्यक जानकारियां 31 मार्च या उसके बाद प्रस्तुत करनी थी, उनकी अंतिम तिथि भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। विस्तार संबंधी आदेश उन सभी क्रेता-विक्रेता अनुबंधों पर भी लागू होगा जो गत 15 मार्च के पहले संपादित हुए हैं, पर जिनकी पूर्णता अवधि 15 मार्च के बाद नियत है। ऐसे अनुबंधों के लिए सहमत निर्माण अवधि में छह माह का विस्तार मान्य किया जाएगा।

मानसून से पहले बाढ़ संभावित क्षेत्रों में करें पूरी तैयारी

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में जुलाई से सितंबर माह में मानसून के दौरान बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी इंतजामों को सुनिश्चित करने के लिए कमिश्नर और कलेक्टर को प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।

राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा है कि ऐसे गांव की संख्या और क्षेत्र जो वर्षाकाल में बाढ़ की दृष्टि से संवेदलशील क्षेत्र है को चिन्हित किया जाये। इसके साथ ही ऐसी नदियों जिनमें बाढ़ आती है उनकों भी चिन्हित करें। वह नदिया जो प्रदेश सहित अन्य राज्यों में बहती हैं उन पर भी ध्यान रखा जाए। बड़े तालाब और नाले जिनसे बाढ़ आने की संभावना रहती है, उनको भी चिन्हित किया जाए। इसके अलावा सभी बड़े बाँधों की सूची तैयार की जाये और जल संसाधन विभाग से इन बांधों को बाढ़ और अतिवृष्टि को ध्यान में रखकर किये गये सुदृढ़ीकरण के कार्य और जिले में बाढ़ आने के मुख्य कारणों की जानकारी एकत्रित कर शासन को भिजवाएं।

पीएस राजस्व ने सभी कमिश्नर व कलेक्टर को दिए निर्देश

प्रमुख सचिव ने कहा कि जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थित प्राकृतिक जलाशयों और जल निकास की नालियों की साफ-सफाई, तालाबों से अतिक्रमण हटाने और तालाब, नालों और बांधों के तटबंधों का निरीक्षण कर उनका सुदृढ़ीकरण भी किया जाए। बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों में नागरिकों को सूचना देने के लिये व्यवस्थित प्रणाली बनाई जाये। बाढ़ और अतिवृष्टि के दौरान की जाने वाली आपातकालीन कार्यवाहियों के लिये जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन दल का गठन करें और जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठके आयोजित की जाएं।

आवश्यक सेवाएं जैसे ऊर्जा, संचार, सड़क और पुल आदि के रख-रखाव की स्थिति की समीक्षा की जाए। सभी विभागों से बाढ़ से निपटने के लिए बनाए गए नोडल अधिकारियों के नाम, पता, दूरभाष, मोबाइल नंबर, फैक्स और ई-मेल की जानकारी भी पहले से संकलित की जाए। बाढ़ प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का आकलन कर क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं दवाइयां आदि का पर्याप्त मात्रा में भंडारण सुनिश्चित किया जाए।

इसके साथ ही बाढ़ की स्थिति में राहत शिविर लगाने की स्थिति पैदा होने पर शिविरों के लिये स्थान आदि भी पहले से तय करा लें। बाढ़ में राहत और बचाव में काम आने वाले उपकरण जैसे नाव आदि की तैयारी पहले से रखें। बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्य में जिनकी सेवाएं ली जाना है उन्हें प्रशिक्षित भी करें। जिला मुख्यालय पर आपदा नियंत्रण केंद्र की स्थापना करें जो 24 घंटे सक्रिय रहें।

लॉकडाउन के गवाह...

कोरोना महामारी के मद्देनजर लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के गवाह इंसान ही नहीं प्रकृति भी इसकी साक्षी बनने की ओर अग्रसर है। लॉकडाउन के चलते जहां देशभर में ट्रेनों का संचालन करीब 40 दिनों से पूरी तरह से बंद है। इसी के चलते रेलवे ट्रेक के बीचोंबीच उगे इस सूरजमुखी के पौधे को फूलने-फलने का पूरा मौका मिल गया है।

यूपी में अब कोरोना वारियर्स से अभद्रता पड़ेगी महंगी

योगी मंत्रीमंडल ने दी अध्यादेश को मंजूरी

लखनऊ, (एजेंसी)। कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू लाकडाउन के कारण राजस्व में आई कमी की भरपाई उत्तर प्रदेश सरकार कर बढ़ोतरी के जरिए करेगी, वहीं कोरोना वारियर्स से अभद्रता करने वालों को लंबी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दस प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार के इस निर्णय से राज्य में पेट्रोल की कीमतें दो रुपए प्रति लीटर और डीजल के मूल्य में एक रुपए प्रति लीटर का इजाफा होगा, वहीं शराब की कीमतों में पांच रुपए से 400 रुपए तक की बढ़ोत्तरी मध्यरात्रि के बाद लागू हो जाएगी। सूबे के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उप्र लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गयी है। उन्होने बताया कि बैठक में अध्यादेश के तहत डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों के साथ ही सरकार की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वारियर्स से की गई अभद्रता या हमले पर छह माह से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान और पचास हजार से लेकर पांच लाख तक का जुर्माना हो सकता है। नए अध्यायदेश के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें मुख्य सचिव सहित सात अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। राज्य प्राधिकरण महामारी के रोकथाम नियंत्रण से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देगा।

अंग्रेजी शराब 400 रुपए तक महंगी

आबकारी नीति के तहत देशी शराब के दाम में पांच रुपए प्रति बोतल की मामूली बढ़ोत्तरी की गई है, जबकि अंग्रेजी शराब के दाम दस रुपए से 400 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। नई कीमतों में 180 एमएल शराब दस रुपए, 500 एमएल 20 रुपए और 500 एमएल से अधिक 30 रुपए महंगी मिलेगी। रेगुलर विदेशी शराब 180 एमएल तक 20 रुपए, 500 एमएल तक 30 रुपए और 500 एमएल से अधिक 50 रुपए महंगी मिलेगी। विदेशी इंपोर्टेड शराब अब 180 एमएल तक 100 रुपए, 500 एमएल तक 200 रुपए और 500 एमएल से अधिक 400 रुपए महंगी मिलेगी। इससे सरकार को 2359 करोड़ रुपए का फायदा होगा।

सरकारी प्रयोगशाला में पाजिटिव और निजी लैब में नेगेटिव आई पत्रकार की रिपोर्ट

वडोदरा, (एजेंसी)। गुजरात के वडोदरा शहर में कुछ दिन पूर्व सरकारी प्रयोगशाला में जांच के दौरान कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए चार स्थानीय पत्रकारों में से एक नीरज पटेल की निजी प्रयोगशाला में करायी गयी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

नीरज समेत चार पत्रकारों की सरकारी प्रयोगशाला में हुई जांच की गत 29 अप्रैल को पाजिटिव रिपोर्ट आई थी। उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) की ओर से मान्य अहमदाबाद की एक निजी प्रयोगशाला में भी बाद में जांच कराई और दो दिन पहले उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आयी। उन्होंने बुधवार को जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि जांच रिपोर्ट पाजिटिव आने के बाद भी उन्हें किसी तरह के लक्षण नहीं दिखे तो उन्होंने निजी लैब में भी जांच कराने की बात सोची। अब इसके नेगेटिव आने पर भी वह तय प्रोटोकॉल के अनुरूप एक बार फिर अपनी जांच कराएंगे और अलग थलग रहने यानी क्वारंटाइन के नियमों का पूरा पालन करते रहेंगे।

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा

एक लाख से अधिक गांवों में जागरूकता पर फोकस

सवा दो करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड किए गए वितरित

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को खेती-किसानी के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने जैविक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग पर मिशन मोड में जागरूकता अभियान द्वारा एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को किसानों के लिए आंदोलन बनाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यक्रम का प्रमुख फोकस देश के सभी जिलों को कवर करने वाले एक लाख से अधिक गांवों में किसानों के लिए जन-जागरूकता अभियान पर होगा। बैठक में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ का प्रचार-प्रसार करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि केवीके-एसएयू के माध्यम से एक लाख गांवों में बड़े पैमाने पर मृदा परीक्षण आधारित उर्वरकों के उपयोग बारे में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कृषि में शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों आदि द्वारा ग्रामीण स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी।

श्री तोमर ने कहा कि उचित कौशल विकास के बाद रोजगार सृजन को सक्षम करने पर यह कार्यक्रम केंद्रित होगा, जैसी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है। जिलों में उन स्थानों पर, जहां प्रयोगशालाएं अभी नहीं हैं, वहां मृदा परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने पर उन्होंने जोर दिया। सुरक्षित पौष्टिक भोजन के लिए भारतीय प्राकृत कृषि पद्धति सहित उर्वरकों के जैविक परीक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी परीक्षण पर आधारित व्यापक अभियान पंचायत राज, ग्रामीण विकास और पेयजल तथा स्वच्छता विभागों के साथ मिलकर चलाया जाएगा।

कार्यक्रम की खास बातें

राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम और उसकी उर्वरता योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2014-15 के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में शुरू किया गया है। मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा कृषि लागत को कम करने के लिए किसानों की सहायता के लिए उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। उर्वरक प्रक्रिया में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए देश के सभी किसानों को प्रत्येक 2 वर्ष के अन्तराल पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। क्षमता निर्माण, कृषि छात्रों की भागीदारी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के साथ प्रभावी लिंकेज के माध्यम से मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसटीएल) के कामकाज को सुदृढ़ करना। राज्यों में समान रूप से नमूना लेने, मृदा विश्लेषण और उर्वरक संस्तुतियां प्रदान करने हेतु मानकीकृत प्रक्रियाओं के साथ मृदा की उर्वरता संबंधी बाधाओं का निदान। पोषक तत्व उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए पोषक तत्व प्रबंधन का विकास व संवर्धन। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों की क्षमता का निर्माण करना। मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्षारीयता, वृहत-पोषक तत्व (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैशियम) और सूक्ष्म पोषक तत्व (जिंक, लौह, तांबा, मैंगनीज तथा बोरॉन) जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों का विश्लेषण।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.